कार के परिवर्तनों (ओ. एल. टी. सी.) का उपयोग नहीं किए जाने से ये उन ट्रांसफार्मरों को दोषपूर्ण बना देते हैं।

8. वोल्टेज को अस्थिरता से बचने के लिए स्वचालित प्रणाली का डिजाइन करते समय भार सम्प्रेषण केन्द्रों के लिये महत्वपूर्ण डाटा की टेलीमीटरी पूर्व अपेक्षित है। जब तक प्रेषण केन्द्रों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है तब तक विद्युत उत्पादन में वोल्टता की अस्थिरता का सामना करने के लिए लोड शेडिंग तथा रि-शिड्यूलिंग का सहारा लिया जाता रहेगा।

9. सभी 132 के. वी. लाइनों तथा 132/एल.वी. ट्रांसफार्मरों में एम. वी. ए. आर. मीटर होने चाहियें क्योंकि प्रणाली संबंधी अध्ययन कार्यों हेतु इस समय वास्तविक प्रतिक्रियाशील विद्युत संबंधी आंकड़े प्राप्त करने में बधाएं आ रही हैं।

10. अधिक उतार-चढाव (ओवर-फ्लक्सिंग) वितरण ट्रांसफार्मरों के खराब होने का एक प्रमुख कारण है तथा इसके बारे में निर्माताओं से बातचीत की जानी चाहिये ताकि ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

11. ट्रांसफामरों में "लघुपथन" संबंधी जांच आवश्यक रूप से कराई जानी चाहिये।

12. पूर्णत: स्वत: सुरक्षित (सी. एस. पी.) ट्रांसफार्मरों पर समन्वय संबंधी जांच आवश्यक रूप से करवाया जाये।

13. सोलिड स्टेट एनर्जी मीटरों के लिए मानक के निर्धारण को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना बनाया जाए।

World Bank for new power projects

159. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of POWER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 225 given in the Rajya Sabha on the 24th November, 1992 and state whether Government have approached the World Bank for financing, New power projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): Discussions are being held with the World Bank for seeking financial assistance for NTPC under a time slice arrangement for its various projects and for the Power Grid Corporation of India for certain transmission lines. Since under this arrangement, there is flexibility in the list of projects for which financing could be utilised, project selection would,, inter alia, depend on the readiness in terms of availability of clearances etc.

Capacity utilisation in different power sectors

160. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what are the details of the capacity utilisation in different power sectors during the first half of the current financial year and how do these compare with the figures of corresponding period during the last two years; and

(b) what steps are being contemplated by Government to improve the capacity utilisation of power plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The details of capacity utilisation PLF of thermal and Nuclear Power Stations in the different power sectors during the period April-

sept., 92 and the corresponding period of the last two years are as under:—

PLANT LOAD FACTORS (%)

	April– Sept. 92 (1992-93)	April—Sept. 91 (1991-92)	April—Sept. 90 (1990-91)
THERMAL			
Central Sector . . .	56.8	59.2	54.7
State Sector . . .	51.0	47.5	48.8
Private Sector . . .	61.7	59.6	62.3
All India	53.5	51.8	51.3
NUCLEAR			
Central Sector . . .	42.4	38.1	48.7

Generation from Hydro and Gas Stations depends upon the availability of water, gas, and system load conditions.

(b) Various measures being taken for optimum utilisation of the installed capacity in the country include Renovation and Modernisation of old units, assistance to Electricity Boards in undertaking plant betterment programmes, supply of requisite quantity ond qcality of coal training of operation and maintenance personnel and strengthening of Transmission and Distribution System.

उत्तर प्रदेश में सिंगल पांइन्ट विद्युत कनेक्शन योजना

161. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिंगल पाँइन्ट विद्युत कनेक्शन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) हरिजन और आदिवासियों समेत गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले ग्रामीण गरीबों के घरों में सिंगल प्वांइट लाइट कनैक्शन की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए भारत सरकार ने 1988–89 में "कुटीर ज्योति" नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी । इस स्कीम के अधीन जिसका 1988–89 और 1989–90 के दौरान केन्द्रीय अनुदान द्वारा वित्त पोषण किया गया था, लाभ प्राप्त करने वालों का पता लगाने का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया था । इस कार्यक्रम के तहत आंतरिक वायरिंग तथा सर्विस कनैक्शन प्रभारों की प्रारंभिक एक मुश्त लागत, ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) के जरिए अनुदान के रुप में राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को उपलब्ध कराई गई थी ।

(ग) तीन वर्ष अर्थात् 1988–89 से 1990–91 (इस दौरान यह कार्यक्रम प्रारम्भिक रूप से प्रचालनाधीन था) तक के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू० पी० ए स० ई० बी०) द्वारा बताई गई प्रगति का जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है [नीचे देखिए] । चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम को पुन: चालू किया गया है ।